पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग),
भारत सरकार
****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्ली, अग्रहायण 09, 1945
गुरुवार, नवंबर 30, 2023

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी

रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने के लिए इन पूंजीगत अधिग्रहण का 98% घरेलू उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा

एचएएल से हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान एमके 1 ए की खरीद को मंजूरी मिली

भारतीय नौसेना के सतह मंच के लिए मध्यम दूरी की एंटी-शिप मिसाइलों को मंजूरी दी गई

भारतीय फील्ड गन को बदलने के लिए टोड गन सिस्टम के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 30 नवंबर, 2023 को 2.23 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) के संबंध में मंजूरी दी, जिसमें से 2.20 लाख करोड़ रुपये (कुल एओएन राशि का 98%) का अधिग्रहण घरेलू उद्योगों से किया जाएगा। यह 'आत्मनिर्भरता' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा देगा।

डीएसी ने दो प्रकार के टैंक-रोधी युद्ध-सामग्री नामतः एरिया डेनिअल म्यूनिशन (एडीएम) टाइप-2 और टाइप-3 की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया है, जो टैंकों व बख्तरबंद कर्मियों के वाहक एवं दुश्मन कर्मियों को निष्क्रिय करने में सक्षम हैं। इंडियन फील्ड गन (आईएफजी) ने अपना सेवा जीवन पूरा कर लिया है इसीलिए इसको बदलने के लिए, अत्याधुनिक टोड गन सिस्टम (टीजीएस) की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया गया है जो भारतीय सेना के आर्टिलरी बलों का मुख्य आधार बन जाएगा। 155 मिमी आर्टिलरी गन में 155 मिमी न्यूबलेस प्रोजेक्टाइल को उपयोग करने के लिए भी एओएन दिया गया, इससे प्रोजेक्टाइल की घातकता

और सुरक्षा बढ़ेगी। भारतीय सेना के ये सभी उपकरण खरीद (इंडियन-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत खरीदे जाएंगे।

खरीद (भारत) श्रेणी के तहत टी -90 टैंकों के लिए स्वचालित लक्ष्य ट्रैकर (एटीटी) और डिजिटल बेसाल्टिक कंप्यूटर (डीबीसी) की खरीद और एकीकरण के लिए एओएन भी प्रदान किया गया है जो विरोधी प्लेटफार्मों पर टी -90 टैंकों की लड़ाकू बढ़त बनाए रखने में मदद करेगा। खरीद (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत भारतीय नौसेना के सतह प्लेटफॉर्म के लिए मध्यम दूरी की एंटी-शिप मिसाइलों (एमआरएएचएम) की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान किया गया है। एमआरएएसएचएम की परिकल्पना एक हल्की सतह से सतह मिसाइल के रूप में की गई है जो भारतीय नौसेना के जहाजों पर एक प्राथमिक आक्रामक हथियार होगा।

इसके अलावा, डीएसी ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय सेना के लिए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) और भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एमके 1 ए की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से खरीद (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत एओएन को मंजूरी दी। डीएसी द्वारा एचएएल से स्वदेशी रूप से एसयू-30 एमकेआई विमान के उन्नयन के लिए एओएन भी प्रदान किए गए हैं। इन उपकरणों की खरीद से भारतीय वायुसेना को काफी मजबूती मिलेगी, वहीं घरेलू रक्षा उद्योगों से अधिग्रहण स्वदेशी क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) पर निर्भरता को भी काफी हद तक कम कर देगा।

स्वदेशीकरण को अधिकतम करने के लिए, डीएसी ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 में एक बड़े संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है। यह निर्णय लिया गया है कि अब से खरीद मामलों की सभी श्रेणियों में सामग्री, घटकों और सॉफ्टवेयर के रूप में न्यूनतम 50% स्वदेशी वस्तुएं होंगी। स्वदेशी सामग्री की गणना के उद्देश्य से, वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी)/व्यापक रखरखाव अनुबंध (सीएमसी)/बिक्री पश्चात सेवा की लागत को बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा, डीएसी ने रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में स्टार्ट-अप/एमएसएमई की भागीदारी को और प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। 300 करोड़ रुपये तक की एओएन लागत वाले सभी खरीद मामलों के लिए, पंजीकृत एमएसएमई और मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को वित्तीय मापदंडों की किसी शर्त के बिना प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करने पर विचार किया जाएगा, जिसे मामला-दर-मामला आधार पर 500 करोड़ रुपये तक की एओएन लागत के लिए रक्षा खरीद बोर्ड (डीपीबी) के अनुमोदन के साथ आगे ढील दी जा सकती है।

एबीबी/एसएस